प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

02.12.2025 / प्रादेशिक समाचार / 19:45 बजे

'' मुख्य समाचार''

- राज्य पथ परिवहन निगम के घाटे में चल रहे चार सौ 35 बस रूट बंद करेगी प्रदेश सरकार–निगम को हर महीने हो रहा 70 करोड़ रूपए का घाटा।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा–जरूरत पड़ने पर करूणामूलक आधार पर रोजगार की नीति में बदलाव करेगी सरकार।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर मंडी में प्रस्तावित जश्न को अमानवीय दृष्टिकोण करार दिया।
- मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को और गति देने के अधिकारियों को दिए निर्देश।
- शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में चल रहा राष्ट्रीय सिल्क एक्सपो लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र।

प्रश्नकाल

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य पथ परिवहन निगम में युक्तिकरण कर घाटे वाले 4 सौ 35 बस रूट बंद करेगी। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक संजय अवस्थी के एक सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए ये बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी को हर माह 70 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इस तरह निगम का सालाना घाटा 8 सौ 40 करोड़ रुपए है और यह घाटा बढ़कर अब तक 2 हजार 2 सौ करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार परिवहन निगम को हर साल 7 सौ 80 करोड़ रुपए अनुदान दे रही है और निगम के बढ़ते घाटे को देखते हुए सरकार कुछ रूटों को बंद कर उन्हें निजी क्षेत्र में देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने परिवहन निगम के वही रूट बंद किए हैं, जहां अतिरिक्त बसें चल रही थी और घाटे में थी। इससे पहले, मूल प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कंधर–बागा बस सेवा को फिलहाल चंडीगढ़ तक ही चलाया जाएगा और इसे फिर से दिल्ली के लिए बहाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम पर इस समय 13 सौ करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी है।

,विधायक सुधीर शर्मा, रणवीर सिंह निक्का और मलेंद्र राजन के संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2016 से 2021 के बीच रिटायर हुए होमगार्ड को उनके वेतन और पेंशन का एरियर प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भुगतान वित्तीय परिस्थितियों पर निर्भर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने स्तर पर राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने पर काम कर रही है और इसमें केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। प्रश्नकाल के दौरान आज सदन में करूणामूलक रोजगार का मुद्दा भी गूंजा और इस मुददे पर सत्ता पक्ष व विपक्ष आमने–सामने हुए। विपक्ष के सदस्य दीप राज के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार करूणामूलक आधार पर रोजगार की नीति में बदलाव करेगी। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने करूणामूलक आधार पर रोजगार के लिए सालाना आय सीमा को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर दिया है। इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार से जानना चाहा कि कांग्रेस सरकार के तीन वर्षों में अनुकंपा के आधार पर दिए गए रोजगार व पूर्व भाजपा सरकार के पांच साल में दिए गए रोजगार के आंकड़े सदन में रखे।

नियम 130

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के मौके पर मंडी में प्रस्तावित जश्न को सरकार का अमानवीय दृष्टिकोण करार दिया है। विधानसभा में आज आपदा पर नियम 130 के तहत हो रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए उन्होंने सरकार से मंडी में सेलिब्रेशन के सभी कार्यक्रम रद्द करने की मांग की। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता–

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के मौके पर आयोजित किए जाने वाले जश्न को पूरी तरह अमानवीय करार दिया है। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आपदा पर नियम 130 के तहत हो रहे मैराथन मंथन में उन्होंने कहा कि सरकार इस जश्न पर बेवजह पैसा खर्च न करे, इसके बजाय यह पैसा आपदा पीड़ितों के राहत व पुनर्वास पर खर्च किया जाए। जयराम ठाकुर ने सरकार के सत्ता में तीन वर्ष पूरा करने के मौके पर मंडी में होने वाले जश्न को स्थगित करने और इसके लिए कोई दूसरा स्थान चयनित करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आपदा के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में डिजास्टर एक्ट लागू है, लेकिन सरकार उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 15 सौ करोड़ रुपए के राहत पैकेज को इसलिए राज्य सरकार के खाते में मांग रही है ताकि वह इस पैसे से वेतन–भत्ते दे सके और सरकार चलाने के लिए इस पैसे को खर्च कर सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चर्चा में दखल देते हुए कहा कि सरकार मंडी में सत्ता में तीन साल पूरा होने पर जश्न नहीं, बल्कि जन संकल्प रैली आयोजित कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार की इस जन संकल्प रैली पर डिजास्टर फंड से कोई पैसा खर्च नहीं होगा और रैली का सारा खर्च राज्य सरकार के खजाने से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जन संकल्प रैली पर कम से कम खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आपदा राहत में कोई भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने इसके लिए भाजपा से भी सहयोग मांगा।

संशोधन विधेयक

राज्य सरकार प्रदेश में भू–अधिनियम की धारा 118 का सरलीकरण करेगी। कारोबार में सुगमता के उद्देश्य से सरकार ने टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 118 में संशोधन की तैयारी कर ली है।

इसके मद्देनजर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने एक संशोधन विधेयक आज सदन में प्रस्तुत किया। इस विधेयक के पारित होने के बाद प्रदेश में सौ फीसदी कृषक सदस्यों वाली सहकारी समितियों को भू–अधिनियम की धारा 118 के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। सहकारी समितियों को मिलने वाली इस छूट से प्रदेश में रोजगार सृजन के साथ–साथ नए उद्यमों की स्थापना में तेजी आएगी। ग्रामीण इलाकों में भी 10 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर इमारतें लेने की छूट होगी।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को और अधिक गति देने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, ताकि चिट्टा सहित अन्य मादक पदार्थों को प्रदेश में पूरी तरह खत्म किया जा सके। वे आज धर्मशाला में नारकोटिक्स को–ऑडिनेशन सेंटर की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने युवाओं अभिभावकों पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों महिला मंडलों व अन्य स्वयं सेवी संगठनों से प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में 24 करोड़ 47 लाख रूपए की लागत से निर्मित समृद्धि भवन का लोकार्पण भी किया।

सिल्क एक्सपो

शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित राष्ट्रीय सिल्क एक्सपो में पारंपरिक साड़ियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। 18 दिसम्बर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में देश भर के बुनकर अपनी कला और परंपरा से जुड़े खास उत्पाद लेकर पहुंचे हैं। इस प्रदर्शनी के कोऑर्डिनेटर जितेंद्र चोपड़ा ने बताया कि केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी में करीब 35 स्टोल लगाए गए हैं।

सिकंदर कुमार

केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद येशोनाईक ने कहा है कि बीते दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में एनएचपीसी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत कुल एक सौ 82 लड़कियों को स्वरोजगार किट प्राप्त हुई है।

राज्य सभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा आज संसद में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि लड़कियों को स्वरोजगार किट के वितरण के माध्यम से सीएसआर पहुलाओं का उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना व उद्यमिता के माध्यम से स्थाई आजीविका की ओर बढ़ने में सक्षम बनाना है।

उन्होंने चंबा में एनएचपीसी सीएसआर पहल के तहत स्वरोजगार किट वितरण से संबंधित ब्यौरा भी सदन में प्रस्तुत किया।

हिरोशिमा विश्वविद्यालय

जापान के हिरोशिमा विश्वविद्यालय के शोधार्थियों की एक टीम ने कृषि निदेशालय शिमला में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की राज्य परियोजना इकाई का दौरा किया। इस दौरान योजना के राज्य नोडल अधिकारी व अतिरिक्त निदेशक कृषि डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा ने इन शौधार्थियों को प्रदेश के कृषि क्षेत्र की विशेषताओं से अवगत करवाया।

'' मुख्य समाचार एक बार फिर''

- राज्य पथ परिवहन निगम के घाटे में चल रहे चार सौ 35 बस रूट बंद करेगी प्रदेश सरकार–निगम को हर महीने हो रहा 70 करोड़ रूपए का घाटा।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा–जरूरत पड़ने पर करूणामूलक आधार पर रोजगार की नीति में बदलाव करेगी सरकार।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर मंडी में प्रस्तावित जश्न को अमानवीय दृष्टिकोण करार दिया।
- मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को और गति देने के अधिकारियों को दिए निर्देश।
- शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में चल रहा राष्ट्रीय सिल्क एक्सपो लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र।